B-2

L-33

भूदान आन्दोलन

पृष्ठभूमि-

- आजादी के बाद सामाजिक, आर्थिक विषमता को कम करने का एक मौलिक प्रयास भूदान आन्दोलन के रूप में सामने आया। वस्तुतः गाँधी के ट्रस्टीशिप सिद्धांत व सर्वोदय की भावना को व्यवहारिक धरातल पर लाने का भूमि व जल प्राकृतिक उपहार हैं अतः इस पर सबका अधिकार होना चाहिए। भारतीय समाज में प्रचलित कहावत "सबै भूमि गोपाल की" की भावना से प्रेरित विनोबा ने सम्पन्न वर्ग से स्वेच्छा पूर्वक जमीन प्राप्त कर उसे भूमिहीनों व निर्धनों में वितरित करने का लक्ष्य रखा।
- 1950 की परिस्थितियों पर नजर डालें तो अधिकांश जनसंख्या ग्रामीण थी, कृषि पर निर्भर थी तथा रोजगार का अभाव था। इसके साथ ही विभाजन की परिस्थितियों से उत्पन्न शरणार्थी समस्या सामाजिक, आर्थिक परिस्थितियों को और विस्फोटक बना रही थी। और भूदान आन्दोलन इन सभी समस्याओं के नैतिक हल का प्रयास था।
- औपनिवेशिक शासन की नीतियों के कारण भू-स्वामित्व के सन्दर्भ में असमानता व्यापक हो गई थी एक तरफ तो किसी के पास हजारों एकड़ की जमीन का स्वामित्व था तो दूसरी तरफ बहुत बड़ी संख्या में लोग भूमिहीन थे। अतः भारत के सशक्तीकरण

KGS IAS KHAN GLOBAL STUDIES Most Trusted Learning Platform KHAN SIR

के लिए आवश्यक था " कि जमीन का वितरण तार्किक व सामाजिक समता पर आधारित हो यदि जमीन के वितरण पर ध्यान नहीं दिया जाता तो हिंसक विद्रोह शुरू होजाते जो जन्मोदित आजाद भारत के लिए अनुचित होता। अतः भूदान इस समस्या के हल का एक अहिंसक व नैतिक प्रयास था।

प्रक्रिया - 1951 में आचार्य विनोबा ने आन्ध्र के पोचमपल्ली गाँव में भूदान आन्दोलन की शुरुआत की जहाँ रामचंद्र रेड्डी नामक जमींदार ने अपनी जमीन दान कर इस आन्दोलन को गति प्रदान की आचार्य विनोबा ने आह्वान किया कि गरीबी और हिंसक विद्रोहों के प्रति हमें संवेदनशील होना चाहिए और इसका बेहतर उपाय है - भूदान

इस आन्दोलन में धनी वर्ग से अपनी जमीन का 1/6 हिस्सा दान करने को प्रेरित किया गया।

सम्पूर्ण भारत की कुल 30 करोड़ एकड़ जोत भूमि में से 5 करोड़ एकड़ जोत भूमि प्राप्त कर उसे गरीबों और भूमिहीनों में वितरित करने का लक्ष्य रखा गया। 1960 का दशक आते आते यह आन्दोलन न सिर्फ लोकप्रिय हुआ बल्कि उत्तरप्रदेश उड़ीसा, बिहार जैसे राज्यों में भी प्रसारित होने लगा।

जहाँ जे० पी० जैसे नेतृत्व कर्ताओं के प्रयासों से यह शीघ्र ही भूदान से ग्राम दान में रूपान्तरित होने लगा और लगभग 4500 ग्राम दान प्राप्त हो चुके थे।

KGS IAS
KHAN GLOBAL STUDIES
Most Trusted Learning Platform
KHAN SIR

किन्तु आरम्भिक सफलताओं के बाद यह आन्दोलन कमजोर पड़ने लगा विशेषत: ग्राम दान की ओर बढ़ना एक जटिल कार्य साबित हुआ क्योंकि सामूहिक लाभ की भावना को अपनाना आसान नहीं था तथा यह समस्या भी देखी गई कि दान में प्राप्त अधिकांश भूमि बंजर थी या फिर विवादों में फंसी हुई थी यही कारण था कि 40 लाख एकड़ जमीन प्राप्त होने के बावजूद केवल 42 हजार एकड़ की जमीन ही वितरित की जा सकी जो अपने लक्ष्य से काफी पीछे रह गया और धीरे-धीरे यह आन्दोलन समाप्त हो गया।

यद्यपि भूदान आन्दोलन अपने वांछित लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सका किन्तु सामाजिक-आर्थिक विषमता को दूर करने का यह एक सकारात्मक व नैतिक, ऐतिहासिक उदाहरण बन गया। आजादी के बाद यह भूमि सुधार का पहला महत्वपूर्ण प्रयास था। और कानून की बजाय भारतीय समाज की सामूहिकता व नैतिकता के आधार पर ऐसा करने का प्रयास इसे अद्वितीय बनाता है।

KGS IAS
KHAN GLOBAL STUDIES
KHAN SIR

राज्यों का पुनर्गठन

पृष्ठभूमि :-

आजादी के बाद समकालीन परिस्थितियों में सशक्त भारत के निर्माण के लिए इसे मजबूत संघीय रूप देना आवश्यक हो चला था और ऐसे में राज्यों के पुनर्गठन का आधार क्या हो इसे निश्चितता प्रदान करना हमारे नेतृत्वकर्ताओं के समक्ष एक प्रबल चुनौती बना और इसी सन्दर्भ में एक विकल्प, भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन का भी उभरा।

उल्लेखनीय है कि स्वतंत्रता संग्राम के दौरान कांग्रेस का दृष्टिकोण भाषाई राज्य के पक्ष में रहा था। 1917 में कांग्रेस ने इसी आधार पर आन्ध्र प्रकोष्ठ की स्थापना की और 1920 के नागपुर अधिवेशन में इसे आधिकारिक स्वीकृति दे दी।

1928 की नेहरू रिपोर्ट में भी भाषायी आधार पर राज्यों के गठन का समर्थन किया गया था।

आजादी के बाद

- स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जब राज्यों के पुनर्गठन का प्रश्न उभरा तो भाषाई आधार की व्यवहारिकता तय करने के लिए सर्वप्रथम धर आयोग का गठन किया गया। इस आयोग ने प्रशासनिक सुविधा के आधार

KGS IAS
KHAN GLOBAL STUDIES
KHAN SIR

पर पुनर्गठन को उचित ठहराया किन्तु भाषायी आधार को तार्किक नही माना।

जनता के बढ़ते दबाव के बीच इस समस्या के हल के लिए जे.वी.पी समिति का गठन किया गया जिसमें सुझाव दिया की जनता की आपसी सहमति तथा आर्थिक व प्रशासनिक व्यवस्था पर बल देते हुए भाषाई आधार को स्वीकारना चाहिए किन्तु अभी निश्चित प्रक्रिया नही बनी है अतः वर्तमान परिस्थितियों में भाषाई आधार को नही स्वीकारा जा सकता।

इन्ही परिस्थितियों में मद्रास प्रांत में तेलगू भाषा के लोगों का अलग राज्य की मांग को लेकर आन्दोलन उग्र होने लगा था और गांधी-वादी नेता श्री रामलू ने 56 दिन के अमरण अनशन से इस मांग को लेकर जब प्राण त्याग दिए तो स्थिति विस्फोटक हो गई और विवश होकर भाषाई आधार पर आन्ध्र प्रदेश को भारत का पहला राज्य बना दिया।

1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग फजल अली, कुंजरू व पाण्डेकर के नेतृत्व में गठित की गई जिसने राज्य पुनर्गठन के लिए निम्न लिखित आधारों को महत्वपूर्ण माना।

A- राष्ट्रीय एकता
B- आर्थिक व प्रशासनिक व्यवहारिता
C- आर्थिक विकास

KGS IAS

अल्प संख्यकों के हितों आधार पर
e- भाषाई आधार पर।

इस तरह भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन को लेकर अनिश्चितता बनी रही और इन्हीं मानकों के आधार पर 14 राज्य व 6 केन्द्र शासित प्रदेश गठित किए गए।

भाषाई आधार पर राज्यों के गठन की समीक्षा

- आजादी के बाद जिस तरह भारत में जातीय व धार्मिक उन्माद फैला हुआ था ऐसे में भाषाई आधार पर राज्यों का गठन आसान छत्र था क्योंकि तत्कालीन परिस्थितियों में कोई दूसरा आधार हमारी एकता व अखण्डता को प्रभावित कर सकता था।
- संघीय ढांचे में सांस्कृतिक विरासत को सुरक्षित रखने का भी यह आधार बना क्योंकि भाषा को प्राथमिकता देने से रीति-रिवाज व संस्कृति को भी संरक्षण दिया जा सकता है।
- भाषाई आधार पर निर्मित राज्यों के बीच विकास की प्रतिस्पर्धा भी देखी गई मद्रास, हैदराबाद, बैंगलोर के बीच बेहतर व विकसित बनने की होड़ लग गई तो गुजराती और मराठी क्षेत्र ने भी विकास की ओर छलांग लगाई किन्तु उत्तर भारत के बड़े राज्य बीमारू की संकलपना में घिरे रहे।

KGS IAS
KHAN GLOBAL STUDIES
Most Trusted Learning Platform
© KHAN SIR

भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की एक सीमा भी है -

भारत विविधता में एकता का देश है। अत: भाषाई आधार पर इसे सीमित करना हमारी सांस्कृतिक परम्परा के अनुकूल नहीं है इसके साथ ही भारत में जनसंख्या की बसावट भी भाषा व बोलियों के आधार पर अत्याधिक मिश्रित रही है। यदि भाषाई आधार पर ही राज्यों का गठन किया जाता तो वह उपास्थित अन्य भाषाई समूह के हितों व अधिकारों का प्रश्न उभरता तथा द्रविड़ नाडु जैसी संकल्पना हमारी एकता व अखण्डता को खतरे में डाल सकती थी। अत: भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन का तर्क सही नहीं माना जा सकता।

KGS IAS
KHAN GLOBAL STUDIES
Most Trusted Learning Platform
KHAN SIR

नीचे से इतिहास लेखन:-

'इतिहास लेखन के दृष्टिकोण में 1970 के दशक में एक नया आयाम उपाश्रयवादी इतिहास लेखन से जुड़ा। इनका मानना था कि अभी तक का इतिहास अभिजात्य वर्गीय दृष्टिकोण से लिखा गया है, उसे ऊपर से इतिहास लेखांकन मानना चाहिए और आदिवासी मजदूर जैसे हाशिए के वर्ग के दृष्टिकोण से अब (इतिहास लेखन) नीचे से इतिहास लेखन को भी महत्व देना होगा।

- वस्तुतः भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में आदिवासी विद्रोहों ने जितनी प्रभावी भूमिका निभाई थी उसे परम्परागत इतिहास लेखन महत्व नहीं देता और अंग्रेजों ने तो इन विद्रोहों को लॉ एण्ड ऑर्डर का विषय मान कर इसकी महानता को मलीन करने का प्रयास किया।
- उपाक्षपवादी विद्वान यह भी मानते हैं कि आम आदमी को एक तरफ ब्रिटिश सत्ता तो दूसरी तरफ अभिजात्य संगठनों (कांग्रेस) से भी जूझना पड़ा इस दृष्टिकोण ने इतिहास लेखन को अवश्य ही समृद्ध बनाया और विशेषतः राष्ट्र निर्माण में आम आदमी की भूमिका को स्थापित करने का प्रयास किया।

KGS IAS
KHAN GLOBAL STUDIES
Most Trusted Learning Platform
KHAN SIR